(b) and (c) The Seventh Plan including allocation of Central assistance to States under the modified Gadgil Formula was approved by the National Development Council in its meeting held on November 8-9, 1985. However, any further change in the formula, based on the views of the State Chief Ministers, could be carried out only if approved by the National Development Council.

Agreement with foreign investigating agency

4051. SHRI GAYA CHAND BHUYAN:

SHRI M. S. GURUPADASWAMY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a special officer of the Directorate of Enforcement was requisitioned by the Ministry recently to visit U.S. to sign an agreement with the foreign investigating agency; and

(b) if so, what is the name of the Agency and on what terms and what particular investigation in foreign countries was entrusted with this firm?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) No, Sir.

(b) In view of (a), the question does not arise.

Raids in Kerala

4052. SHRI K. GOPALAN:

SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) during the last three years how many private financial institutions in Kerala were raided by R.B.I. officials.

(b) year-wise figures and actions taken thereon;

(c) the names of private financial institutions which were raided recently;

(d) whether any indiscriminate evidence was found;

(e) whether any penalty has been imposed on these institutions, if so, details thereof; and

(f) whether any prosecution proceedings has been launched against any one of them, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Reserve Bank of India has reported that during the last three years ending 31-7-1987 it had conducted raids on certain unincorporated bodies as indicated below for suspected violations of the provisions of Chapter III-C of Reserve Bank of India Act, 1934.

Year	No. of Companies raided by RBI	No. of Companies raided jointly with State Govt.	Total
1985	..	..	..
1986	6	..	6
1987	2	73	75

(c) The names of the unincorporated bodies which were raided by Reserve Bank of India and the State Government of Kerala during 1987 are given in the Annexure. [See Appendix CXLIII, Annexure No. 158]

(d) to (f) Reserve Bank of India has reported that after completion of investigations, prosecutions have been launched against four unincorporated bodies.

भारत द्वारा परमाणु हथियारों का बनाया जाना

4053. **श्री रशीद मसूद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रति-रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के निदेशक, श्री के० सुब्रहमण्यम के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि चीनी आक्रमण का सामना करने तथा देश के रक्षा व्यय को कम करने के लिए भारत द्वारा परमाणु हथियार बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1987 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "परमाणु शस्त्र ही चीनी खतरे का जबाव" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के पास परमाणु हथियारों के निर्माण के संबंध में कोई कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) से (ग) सरकार ने इस मामले में श्री सुब्रहमण्यम के विचारों के बारे में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट देखी है। सरकार उनके विचारों से अनिवार्यतः सहमत नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार की नीति परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करने की रही है।

बोफोर्स तोपों की कुशलता संबंधी परीक्षण

4054. **श्री रशीद मसूद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोफोर्स तोपों की कुशलता और उपयोगिता का परीक्षण मध्य प्रदेश में देवलाली स्थित तोपखाने में किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त तोपखाने के अधिकारियों ने आर्मी हैड-क्वार्टर्स, नई दिल्ली को एक रिपोर्ट भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में इन तोपों की कुछ खामियों का उल्लेख किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोफोर्स कम्पनी से इन्हें दूर करने के लिए कहा था ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) से (घ) बोफोर्स तोपें स्कूल आफ आर्टिलरी, देवलाली (महाराष्ट्र) में बहुत से परिचयात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों" के लिए इस्तेमाल की गई थी। इन पाठ्यक्रमों के दौरान इन तोपों की जानकारी न रखने वाले कर्मीदल ने इनका उपयोग किया था। इस उपयोग के दौरान इनमें कुछ छोटी-मोटी खराबियां आ गई थीं जो कि एक नई प्रौद्योगिकी प्रणाली के उपयोग के प्रारम्भिक चरण में असामान्य नहीं हैं। स्कूल आफ आर्टिलरी, देवलाली ने इन खराबियों की सूचना और एक रिपोर्ट सेना मुख्यालय को भेजी कि ठेके के प्रावधानों के अनुसार देवलाली में तैनात बोफोर्स के तकनीशियनों द्वारा ज्यादातर खराबियां दूर कर दी गई हैं। सरकार ने भी बोफोर्स के साथ यह मामला उठाया जिसमें यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि इन तोपों में छोटी-मोटी खराबियां भी न हों ताकि वे हर समय विश्वसनीय तथा दोषमुक्त कार्य करती रहें।